भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4100
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- समायोजित निवल बैंक ऋण

4100. श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के किसानों को अनिवार्य 18 प्रतिशत समायोजित निवल बैंक ऋण का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है; और

(ख) सरकार द्वारा बैंकों को अनिवार्यता का अनुपालन सुनिश्चित करने और छोटे किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 04 सितंबर, 2020 को पी.एस.एल. पर मास्टर डायरेक्शंस के माध्यम से प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग (पी.एस.एल.) पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग (पी.एस.एल.) रेगुलेशन के अनुसार, आर.बी.आई. ने अनिवार्य किया है कि अनुसूचित कमर्शियल बैंक, एडजेस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (ए.एन.बी.सी.) का 18% या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर (सी.ई.ओ.बी.ई.) के बराबर क्रेडिट, जो भी अधिक हो, प्रदान करेंगे; जिसमें से छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक सब-लिमिट निर्धारित की गई है जो वर्तमान में 10% है।

(ख): यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक निर्देशों का अनुपालन करें और छोटे किसानों को ऋण प्रदान करें, बैंकों को छोटे और सीमांत किसानों सहित 'कमजोर वर्गों' के लिए एक सब-लिमिट निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, जिन बैंकों को प्रायॉरिटी सेक्टर को ऋण देने में किसी भी तरह की समस्या है उन्हें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ स्थापित रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आर.आई.डी.एफ.) और नाबार्ड के साथ अन्य फंड्स में योगदान के लिए राशि आवंटित की जाएगी, जैसा कि समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जाता है। आरआईडीएफ से राशि को छोटे और सीमांत किसानों को आगे ऋण देने के लिए नाबार्ड की सीजनल एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस (एस.टी.एस.ए.ओ.) स्कीम के माध्यम से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (डीसीसीबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को री-फाइनेंस किया जाता है।

सरकार, संशोधित ब्याज छूट योजना के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान कर रही है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है।

इस योजना के तहत किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर के.सी.सी. ऋण मिलता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं को 1.5% की अग्रिम ब्याज छूट (आई.एस.) प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, जो किसान अपने ऋणों को समय पर चुकाते हैं, उन्हें 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पी.आर.आई.) मिलता है जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। आई.एस. और पी.आर.आई. का लाभ 3 लाख रुपये तक की ऋण सीमा के लिए उपलब्ध है। हालांकि अगर अल्पकालिक ऋण, संबद्ध गतिविधियों (फसल पालन के अतिरिक्त) के लिए लिया जाता है तो छोटे और सीमांत किसानों की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऋण राशि केवल 2 लाख रुपये तक सीमित है। हालांकि, वर्ष 2025 के बजट में इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है।

*****